1	2	3
20	National Bicycles Corpn. of India Ltd.	0·20
21	National Instruments Ltd.	0·06
22	Scooters India Ltd.	3·21
23	Cement Corpn. of India Ltd.	0·20
24	Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd.	1·00
25	Hindustan Salts Ltd.	
26	Sambhar Salts Ltd.	2·31
27	Tannery & Footwear Corpn. of India	2·25
28	Tyre Corporation of India Ltd.	0·66
29	Engineering Projects (India) Ltd.	2·43
30	National Industrial Dev. Corpn. Ltd.	0·10
31	Bridge & Roof Company Ltd.	0·95

Selling/leasing out of branches by C.C.I.

4721. SHRI RANJAN PRASAD YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Cement Corporation of India, a Pub lic Sector Undertaking, is selling/ leasing out its branches; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) No such decision has been taken yet.

(b) In view of the reply to (a) above, the question doesn't arise.

Incentives for new industries

4722. SHRI J. P. JAVALI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not so far announced any incentives and guidelines for new industries after declaring its New Economic Reforms relating to industrial liberalisation and deregulation;

(b) what are the details of incentives offered to tiny and small scale sector; and

(c) what are the details of Exit Policy announced for sick industries both for large and small scale sectors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL. DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) State Governments through their Industrial Policies offer incentives for attracting industries to their respective states.

(b) Details of incentives offered to small and tiny enterprises are contained in the policy package announced in the Parliament on 6th August, 1991. The incentives offered, inter-alia, included preference in land allocation/power connection access to facilities for skill/technology upgradation and institutional finance, priority in Government purchase programme,

equity participation by other industrial undertakings in small scale units upto 24 per cent.

(c) Under the new Industrial Po licy, Government has ensured that the interest of labour would be fully protected. In order to do this, a Na tional Renewal Fund has been esta blished which will act as a social security net to protect the interest of workers against the effects of tech nology upgradation and modernisa tion.

लघु पैमाने के उद्योग

4723. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो दशकों के दौरान देश में लघु पैमाने के उद्योगों की संख्या में 250 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में कार्यरत कुल कर्मकारों में से 38 प्रतिशत कर्मकार इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लघु पैमाने के क्षेत्र में पूंजी निवेष बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में उद्योगों की पूंजी निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सरकार को अनेक सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) लघु औद्योगिक एककों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) की अनुमानित संख्या 1973–74 में 4.16 लाख थी, जो 1990–91 के अंत में बढ़कर 19.38 लाख हो गयी, जिससे इस अवधि के दौरान इनमें 365% की वृद्धि हुई है।

(ख) यद्यपि बड़े और छोटे औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन 1990–91 के अंत में लघु क्षेत्र में 124.30 लाख रोजगार होने का अनुमान है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वर्ष 1987–88 के लिए किये गए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1987–88 को समाप्त वर्ष में कारखाने की अचल संपत्तियों के अवमूल्यित मूल्य द्वारा यथा निरूपित प्रति श्रमिक औसत अचल पूंजी 22,125 रु० की थी, जबकि कारखाना अधिनियम में आने वाले बड़े औद्योगिक क्षेत्र में यह राशि 2,20,366 रु. थी।

(घ) और (ङ) लघु क्षेत्र में पूंजी की कमी के बारे में तथा नयी एजेंसियों की स्थापना करके और मौजूदा वित्तीय संस्थाओं के कार्य निष्पादन में सुधार करके उसकी आपूर्ति बढ़ाने के बारे में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों आदि से समय-समय पर अभ्यावेदन तथा ज्ञापन प्राप्त होते हैं।

औद्योगिक रुग्णता

4724. **श्री वीरेन जे. शाह :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता की समस्या दिन प्रति दिन तेज गति से बढ़ती जा रही है ;